

(c) if the answer to part (a) above be in the negative what are the reasons for delay and by when it is likely to be submitted?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH): (a) to (c) The Committee on 'One Rank One Pension' considered all aspects of the issue but was unable to arrive at a consensus. Thereafter, discussions were held with the various concerned Deptts/Ministries and a scheme to provide adhoc increase in pensions to Defence personnel, below officer level, who retired before 1-1-1986, was approved by the previous Government on 1st November 1990. This decision is now reviewed by the present Government.

Production of light attack helicopters

648. SHRI SURESH KALMADI: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 1471 given in the Rajya Sabha on the 21st August, 1990 and state;

(a) whether the feasibility study undertaken by HAL for the production of Light Attack Helicopter has been completed;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative; by when it is likely to be completed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI LALIT VIJAY SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) It is not in Public interest to divulge these details.

(c) Does not arise.

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिये नयी योजनाएं

649. डा. अरार अहमद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए कोई नई योजना बनाई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के कल्याणार्थ अनेक कार्यक्रम चालू हैं जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं—ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना और शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम तथा नेहरू रोजगार योजना ।

अभी तक कोई नई स्कीम तैयार नहीं की गई है ।

अल्पसंख्यकों के लिए पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम

650. डा. अरार अहमद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सरकार भी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम को प्राथमिकता देगी, यदि हाँ, तो क्या सरकार के इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए जिला स्तर पर अधिकारियों को कोई अनुदेश जारी कर दिये है या जारी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार ने हाल ही में देश के अनेक भागों में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत क्या-क्या कदम उठाये हैं और उनका मुद्देवार बयान क्या है ?

श्रीम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल मुमन) : (क) सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्री कार्यक्रम के प्रति गंभीरता से वचनबद्ध है । 15 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मानिटर करने के लिए हाल ही में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल समिति पुनर्गठित की गई है । सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से पुनः अनुरोध किया गया है कि वे समयबद्ध कार्यवाई योजना के अनुसार मुख्य सचिवों के स्तर पर नियमित आधार पर त्रैमासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करें । राज्य सरकारों